

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,  
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-01

देहरादून: दिनांक 30 सितम्बर, 2016

विषय:-

एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या-12415 के अंतर्गत सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम तक एच.टी./एल.टी. लाईन स्थापित किये जाने व एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (परियोजना), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० का पत्र संख्या-1683/निदे.(परिचालन)/उपाकालि/N-1, दिनांक 27.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम तक एच.टी./एल.टी. लाईन स्थापित किये जाने व एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने हेतु ₹ 2636.76 लाख का आगणन धनावंटन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या-12415 Provision of laying underground HT/LT cable between Sonprayag and Kedarnath for providing uninterrupted power supply during yatra हेतु यू.पी.सी.एल. द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त ₹ 2495.42 लाख की धनराशि संस्तुत की गई है।

प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में राज्य योजना आयोग के द्वारा आयोजित व्यय वित्त समिति की दिनांक 15 सितम्बर, 2016 की सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार यू.पी.सी.एल. से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त करते हुए वित्त व्यय समिति के सुझावों के अनुसार इस परियोजना हेतु ₹ 2047.27 लाख की धनराशि पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रोजेक्ट कोड संख्या-12415 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 1340.00 लाख की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई है। अतः इस परियोजना हेतु ₹ 1340.00 लाख (₹ तेरह करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व संक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु 3 Approved निर्माताओं या उनके Authorised distributor से कोटेशन प्राप्त करने के उपरान्त या निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरों पर कार्य कराया जाय।
- 3- कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
- 4- निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का frequency के अनुरूप NABL laboratory से परीक्षण अवश्य करा दिया जाय।
- 5- आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी.एम.आर. की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मर्दें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्यता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मर्दों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मर्दें हैं। यह सही है कि मर्दें डी.एस.आर. में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुये यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मर्दों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।
- 6- परियोजना की अवशेष लागत का भुगतान डी.डी.एम.ए. रुद्रप्रयाग की एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाओं की बचतों से किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा समुचित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख-रखाव एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0108-एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा, 2013) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान-24-वृहद् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।
- 10- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या-2317 (1)/XVIII-(2)/2016-4(21)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा10 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।
8. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून एवं रुद्रप्रयाग।
10. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव